''तुलसी दया
न छाड़िये
जब
लग घट
में प्रान''
-महात्मा गांधी-

दैनिक
लोक जीवन
www.lokjeewan.com
जयपुर एवं भीलवाड़ा से प्रकाशित राज्य स्तरीय समाचार पत्र
संस्थापक - स्व. डॉ. शिवकुमार जी त्रिवेदी

लोक जीवन में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें:-
- : जयपुर : -
0141-4038281
- : भीलवाड़ा : -
8306792625

वर्ष- 19 | अंक- 183 | जयपुर. शनिवार . | 31 अक्टूबर , 2026 | RNI No. RAJHIN/2008/26744 | मूल्य 1 रूपया | पृष्ठ - 4

अनिश्चितता के वर्तमान दौर में भारत का विकास दुनिया के लिए नई उम्मीद- प्रधानमंत्री मोदी

9.34 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात, खातों में आई सम्मान निधि की 24वीं किस्त

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा में विभिन्न लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ कार्य राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 24वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार 690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण और उनके सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी है। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2013-14 के तुलना में कृषि बजट 5 गुना से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि गत 12 वर्षों में केंद्र सरकार की नीतियों से 50 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले या उनकी बचत हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत साढ़े 4 लाख करोड़ रुपये छोटे किसानों के खाते में जा चुके है। वहीं, वैश्विक अनिश्चितता के कारण खाद्य की कीमतें बढ़ी पर इसका बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। खाद्य की सुगम उपलब्धता के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी का वादा पूरा करते हुए गेंहू एवं धान के किसानों के खातों में 24 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। इसी प्रकार पीएम फसल बीमा योजना का सशक्त कवच प्रदान करते हुए किसानों को फसल मुआवजे पर 2 लाख करोड़ रुपये दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसानों का सिंचाई का खर्चा कम हो। इसी क्रम में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को 12 लाख सोलर पम्प दिए गए दिए हैं। इससे किसानों की 80 करोड़ लीटर से अधिक डीजल की बचत के साथ बिजली भी पैदा हुई है। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय में बढ़ोत्तरी और खेती के सामर्थ्य को बढ़ाने पर जोर देते हुए केंद्र सरकार के सार्थक प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि खेती की परम्परा में तकनीक का समावेश करते हुए देशभर के 26 करोड़ से अधिक सोईल हैल्थकार्ड जारी किए गए। वहीं, बदलते मौसम के अनुरूप किसानों को 3 हजार नए किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि पशुपालन और डेयरी में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में दुग्ध उत्पादन तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में एक गाय या भैंस से प्रतिदिन औसतन 5 लीटर से कम दूध मिलता था। यह बढ़कर अब लगभग 8 लीटर हो चुका है। दुनिया में हमारा देश आज दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मछली पालन क्षेत्र में सहकारिता को प्रोत्साहन दिया है। वहीं, देश में मधु क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। हमारा देश प्राकृतिक शहद का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनिश्चितता के वर्तमान दौर में भारत का विकास दुनिया के लिए नई उम्मीद है। केंद्र सरकार का विकास का हर प्रयास भारत को विकसित बनाने के लिए है।



अन्नदाताओं की खुशहाली से ही देश की समृद्धि - मुख्यमंत्री शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं की खुशहाली से ही देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी कर देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इसका लाभ राजस्थान के 66 लाख 59 हजार से अधिक किसान परिवारों को भी मिला है, जिनके खातों में 1,335 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को 23 किस्तों में 29 हजार 99 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है। वहीं, देशभर के किसानों को 4 लाख 47 हजार करोड़ रुपये की सम्मान निधि हस्तांतरित की गई है।

बदरीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 लोगों की मौत

चमोली (एजेंसी)। बदरीनाथ से देहरादून लौट रहा एक हेलीकॉप्टर जोशीमठ के नजदीक पांडुकेश्वर में भेड़ गदेरे की पहाड़ी पर क्रैश हो गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि सेना मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही सेना ने रेस्क्यू की कमान भी संभाल ली है। मृतकों के शवों को लाया जा रहा है। जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार के अनुसार दुर्घटना के कारणों की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पांडुकेश्वर सड़क से 7 किलोमीटर लगभग पैदल रास्ते पर घटनास्थल स्थित है। बताया जा रहा कि बदरीनाथ और ज्योशीमठ के नजदीक पांडुकेश्वर में भेड़ गदेर की पहाड़ी पर यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर ट्रांस भारत कंपनी का है। जिसमें 1 पायलट और 5 यात्री सवार थे। सभी यात्री बेंगलुरू के बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में पायलट हिमांशु, यात्रियों में प्रथापा, अरुण सालुंके, शंकरगौड़ा वीजी, सुधीर के और एच.एस. नागाराजा सवार थे। राहत और बचाव के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी मौके के लिए रवाना हो गई थी। हेलीकॉप्टर बदरीनाथ से देहरादून आ रहा था, जिसे सहस्त्रधारा हेलीपैड पर उतरना था। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के सभी हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। यूकाडा के सीईओ प्रतीक जैन का कहना है कि पायलट से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, टीम घटना स्थल को रवाना कर दी गई है। सीएम धामी ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उक्त हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं।



सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी सही तौल, नए नियम लागू

जयपुर (कासं)। सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 29 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधानों के तहत सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री में निर्धारित मानकों वाले सटीक कांटों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए Class I (विशेष सटीकता) अथवा Class II (उच्च सटीकता) श्रेणी के कांटों का ही उपयोग किया जा सकेगा। इन कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना आवश्यक है। इससे कम मात्रा में भी तौल की सटीकता सुनिश्चित होगी तथा उपभोक्ताओं को खरीदी गई सोना-चांदी की सही मात्रा मिल सकेगी। उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी स्वर्णकारों, सर्राफा व्यापारियों एवं बहुमूल्य धातुओं का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों से नए प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। व्यापारियों को सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए निर्धारित Class I अथवा Class II श्रेणी के कांटों का उपयोग करना होगा। साथ ही, कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना चाहिए। विभाग ने व्यापार में प्रयुक्त कांटों का नियमानुसार सत्यापन करवाने तथा उनका वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र रखने के निर्देश दिए हैं। जिन व्यापारियों के पास वर्तमान में निर्धारित मानकों के अनुरूप कांटे उपलब्ध नहीं हैं।

पंचायत चुनाव में वोटों की बंपर बरसात, 82.47% मतदान

रामपुरा डाबड़ी में सर्वाधिक 84.43 प्रतिशत मतदान



जयपुर(कासं)। पंचायतीराज आम चुनाव के द्वितीय चरण के तहत जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों की 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए शुक्रवार को मतदान कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि सायं 6 बजे तक कुल 82.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस दौरान कुल 3,78,364 मतदाताओं में से 3,12,035 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंचायत समिति क्षेत्र अमरसर में 80.94 प्रतिशत, आमेर में 82.09 प्रतिशत, जालसू में 82.49 प्रतिशत, रामपुरा डाबड़ी में 84.43 प्रतिशत तथा शाहपुरा में 82.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इनमें रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक 84.43 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान के समयवार आंकड़ों के अनुसार प्रात: 10 बजे तक 19.83 प्रतिशत, दोपहर 1 बजे तक 45.17 प्रतिशत, अपराह्न 3 बजे तक 60.53 प्रतिशत तथा सायं 6 बजे तक 82.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कर्मचारियों को दीपावली की सौगात

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी, 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत होगा डीए-डीआर



जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। इस वृद्धि के बाद डीए एवं डीआर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इससे प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारी एवं 5 लाख से अधिक पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

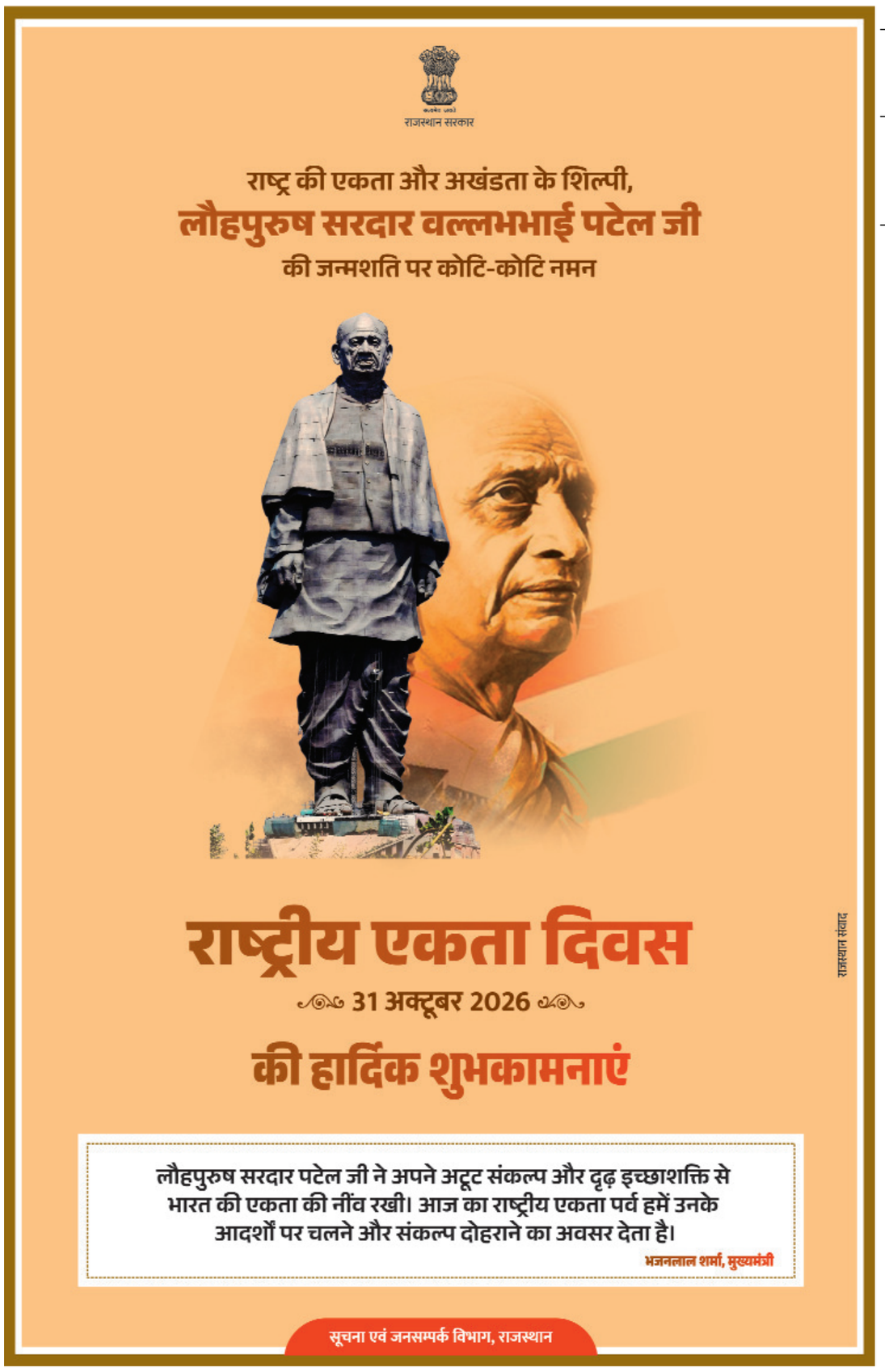
रोशन होगी कर्मचारियों की दीपावली, लाखों परिवारों को मिलेगा संबल: इस निर्णय के तहत सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत का लाभ 1 जुलाई 2026 से देय होगा। कर्मचारियों को आगामी दिसम्बर में देय नवम्बर 2026 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक चार माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी।

पेंशनरों को 01 जुलाई, 2026 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जायेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

दीपावली बोनस का भी उपहार- इसके साथ ही राज्य सरकार ने लगभग 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का निर्णय भी लिया है।

इसके तहत राज्य सरकार पर 406 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इन निर्णयों से कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हितों के संरक्षण और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। कर्मचारी प्रदेश के विकास और सुशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके योगदान को सम्मान देते हुए राज्य सरकार उनके हित में निरंतर निर्णय ले रही है।



पहली कोशिश में विक्रांत पर उतरा राफेल, नौसेना की युद्धक क्षमता को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी युद्धक क्षमता को एक नया आयाम देते हुए एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। फ्रांस निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल मरीन ने गुरूवार को भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर अपनी पहली ही कोशिश में सफल लैंडिंग की है। नौसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने के तौर पर इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि यह लैंडिंग, भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस में इस विमान को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय नौसेना गोवा में राफेल मरीन के फ्लाइट ट्रायल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आईएनएस विक्रांत से इसके संचालन के लिए किन बदलावों की जरूरत है। इन ट्रायल का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या यह विमान



एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरी तरह से काम कर सकता है, और इसे तैनात करने की तैयारी करना है।

बता दें कि भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया था। इसके तहत नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदे जाने थे। इस पैकेज में 22 सिंगल-सीट फाइटर और चार ट्विन-सीट ट्रेनर विमान शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें हथियार, सिम्युलेटर, प्रशिक्षण, जरूरी उपकरण और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल हैं। इन विमानों की डिलीवरी 2030 तक पूरी होनी है, और इसके लिए भारतीय नौसेना के कर्मियों को फ्रांस और भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस समझौते में तकनीक के हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) का प्रावधान भी है, ताकि स्वदेशी हथियारों को इन विमानों में एकीकृत किया जा सके। 63,000 करोड़ रुपये के इस समझौते में भारत में राफेल के 'फ्यूज़लेज' (विमान के मुख्य ढांचे) के उत्पादन की सुविधा स्थापित करना, और इंजनों, सेंसरों व हथियारों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल की सुविधाएं तैयार करना भी शामिल है। वर्तमान में केवल फ्रांसीसी नौसेना द्वारा संचालित, राफेल मरीन को विशेष रूप से विमानवाहक पोतों से घातक संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस विक्रांत पर इसकी तैनाती से भारतीय नौसेना की हवाई सुरक्षा और समुद्र के साथ-साथ जमीन पर सटीक हमले करने की क्षमता में कई गुना इजाफा होगा।

एक ही दिन दिल्ली में दो सियासी मार्च, आमने-सामने होंगे कांग्रेस और भाजपा

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक नवंबर को इंडिया गठबंधन द्वारा बुलाई गई महारैली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे मार्च शुरू होगा। यह मिंटो रोड और कनॉट प्लेस के जंक्शन से शुरू होगा और रामलीला मैदान तक हम सब मिलकर चलेंगे। कांग्रेस नेता ने लोगों से बड़ी संख्या में 'इंडिया' गठबंधन के इस मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 'वोट चोरी' के खिलाफ एक नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक मार्च निकालेगा। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की।

दैनिक लोकजीवन
जयपुर एवं भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित
संस्थापक - स्व. डॉ. विश्वबन्धु जी त्रिवेदी

विद्यार्थियों के सपनों में छिपा है राष्ट्र का भविष्य

विद्यार्थी किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनकी आंखों में पलने वाले सपने, मन में उठने वाले विचार और कर्म में दिखाई देने वाला संकल्प ही देश के भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। आज के विद्यार्थी ही कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासक, उद्यमी, सैनिक और राष्ट्रनिर्माता हैं। इसलिए विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारना, उन्हें सही दिशा देना और उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करना केवल परिवार या शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। इसी संदर्भ में विश्व विद्यार्थी दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत में 15 अक्तूबर को पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणास्त्रोत डा. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा, ज्ञान, अनुशासन, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करना है। डा. कलाम का संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके पास बड़े सपने देखने का साहस और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करने का संकल्प हो। डा. कलाम का जीवन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा : डा. कलाम का जीवन संघर्ष, सादगी, अनुशासन और समर्पण की अनुपम मिसाल है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा के प्रति अपनी लगन को कभी कम नहीं होने दिया। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2002 में वह भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद भी उनका सबसे प्रिय परिचय एक शिक्षक का ही रहा। डा. कलाम का विश्वास था कि बच्चों और युवाओं के भीतर देश को बदलने की क्षमता है। वह विद्यार्थियों से संवाद करते, उनके प्रश्नों को प्रोत्साहित करते और उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा देते थे। उनका जीवन संदेश देता है कि सफलता केवल संसाधनों की प्रचुरता से नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच से प्राप्त होती है। आज जब विद्यार्थी परीक्षा, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितताओं के दबाव से गुजर रहे हैं, तब कलाम के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि अपनी कमियों को पहचानकर आगे बढने का अवसर है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, वर्तमान समय में शिक्षा को अक्सर परीक्षा में प्राप्त अंकों, डिग्रियों और नौकरी हासिल करने के साधन के रूप में देखा जाता है। निस्संदेह, रोजगार प्राप्त करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य इससे कहीं व्यापक है। शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है, सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है तथा समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का बोध कराती है। यदि कोई विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त कर ले, लेकिन उसमें ईमानदारी, संवेदनशीलता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का अभाव हो, तो उसकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य केवल सफल पेशेवर तैयार करना नहीं, बल्कि अच्छे नागरिकों का निर्माण करना भी होना चाहिए। आज आवश्यकता ऐसी शिक्षा व्यवस्था की है, जिसमें किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव, नैतिक मूल्य, संवाद कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान की क्षमता को भी समान महत्व मिले।

विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, नए विचार प्रस्तुत करने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न करने वाला विद्यार्थी ही आगे चलकर अनुसंधानकर्ता और नवाचारक बन सकता है। डिजिटल युग में विद्यार्थी और नई चुनौतियां : इक्कीसवीं सदी का विद्यार्थी ऐसे दौर में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जहां मोबाइल फोन, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल माध्यमों ने ज्ञान तक पहुंच को आसान बना दिया है। आज घर बैठे दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की अध्ययन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल पुस्तकालयों ने सीखने के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। लेकिन इन सुविधाओं के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, मोबाइल पर अनावश्यक समय बिताना, गलत सूचनाओं का प्रसार और डिजिटल मनोरंजन की लत विद्यार्थियों की एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। कई विद्यार्थी दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करके तनाव का अनुभव करते हैं और अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हैं। तकनीक अपने आप में न अच्छी है और न बुरी, उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को डिजिटल साधनों का इस्तेमाल ज्ञान अर्जित करने, नई क्षमताएं विकसित करने और रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। उन्हें यह भी सीखना होगा कि इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक जानकारी सत्य नहीं होती। तथ्यों की जांच करना, विश्वसनीय स्रोतों को पहचानना और अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करना आज की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा का दबाव : विद्यार्थियों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानसिक दबाव भी है। अच्छे अंक प्राप्त करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने और मनचाहा करियर चुनने की दौड़ में कई विद्यार्थी तनाव का सामना करते हैं। कुछ मामलों में अभिभावकों की अत्यधिक अपेक्षाएं और समाज में सफलता की सीमित परिभाषा इस दबाव को और बढ़ा देती है।

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की नीतियाँ आज भी हैं प्रासंगिक और भारत की मार्गदर्शक

मोदी सरकार ने किया राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने और गुजरात के एकता नगर में लौह पुरुष की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य'

-वासुदेव देवनानी -

इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनका महत्व उनके जीवनकाल की घटनाओं तक सीमित नहीं रहता।बल्कि एक कालजयी इतिहास बन जाता है। ऐसे इतिहास पुरुष अपने समय की चुनौतियों का समाधान खोजते हुए ऐसे सिद्धांत स्थापित कर जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल ऐसे ही राष्ट्रनायक थे। स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्षशील सेनानी, असाधारण संगठनकर्ता, कुशल प्रशासक और आधुनिक भारत के राजनीतिक एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार के रूप में उनकी पहचान भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट रखती है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद 562 से अधिक रियासतों के एकीकरण और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में पटेल की निर्णायक भूमिका रही है। आज, जब भारत आर्थिक आकांक्षाओं, सामाजिक विविधताओं, तकनीकी परिवर्तन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के एक नए दौर से गुजर रहा है, तब पटेल की प्रासंगिकता को समझना केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा पर उनके मार्गदर्शक विचारों और नीतियों पर विचार करना भी आवश्यक है।

स्वतंत्रता से राष्ट्र-निर्माण तक : एक असाधारण चुनौती

31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में जन्मे वल्लभभाई पटेल का व्यक्तित्व संघर्ष, अनुशासन और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता से निर्मित हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के बाद उन्होंने गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली आंदोलन में किसानों को संगठित कर अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। बारडोली के किसान आंदोलन ने उन्हें 'सरदार' की उपाधि दिलाई और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पहचान को नई ऊँचाईयाँ मिली । सरदार पटेल की ऐतिहासिक भूमिका का सबसे कठिन अध्याय 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के समय भारतीय उपमहाद्वीप में 562 से अधिक देशी रियासतें थीं जिनमें राजा-महाराजाओं और निजामों आदि का एक छत्र साम्राज्य था । इनके भविष्य का प्रश्न नव स्वतंत्र भारत की अखंडता के सामने एक बड़ी चुनौती था। यदि इन रियासतों का एकीकरण और स्वतन्त्र भारत में विलय नहीं होता, तो भारत का राजनीतिक भूगोल खंडित हो सकता था और राष्ट्रीय एकता,संप्रभुता और विकास की संभावनाएँ गंभीर रूप से प्रभावित होतीं। ऐसे कठिन समय में भारत के तत्कालीन उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने वी. पी. मेनन सहित अपने अन्य सहयोगियों के साथ संवाद, कूटनीति, व्यावहारिक समझ और आवश्यकतानुसार दृढ़ प्रशासनिक कार्रवाई का सहारा लिया। परिणामस्वरूप इन रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य आगे बढ़ा और जूनागढ़ एवं हैदराबाद जैसे जटिल मामलों से निपटने में भी सरदार पटेल की भूमिका निर्णायक रही। सरदार पटेल की यह उपलब्धि बताती है कि राष्ट्र-निर्माण केवल आदर्शों की घोषणा से नहीं होता। उसके लिए दूरदृष्टि, समय पर निर्णय, संवाद की क्षमता और राष्ट्रीय हितों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। पटेल ने इन गुणों का ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया, जो आज भी सरकारों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक नीति और सिद्धांत है।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1949 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर लगे प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था तब गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाने के लिए निर्णायक बातचीत के लिए पहल की थी फलस्वरूप भारत सरकार ने 11 जुलाई 1949 को आरएसएस पर लगाया प्रतिबंध औपचारिक रूप से हटाया था।

दृढ़ता के साथ संवाद : नेतृत्व का वास्तविक अर्थ

सरदार पटेल को 'लौह पुरुष' कहा जाता है। लेकिन उनके व्यक्तित्व की व्याख्या उन्हें केवल कठोरता के प्रतीक के रूप में बताना उचित नहीं है । उनकी राजनीतिक शैली में दृढ़ संकल्प के साथ व्यावहारिकता और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता भी थी। रियासतों के एकीकरण में अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार वार्ता, समझौते और अन्य उपाय अपनाना उनकी इसी दृष्टि को दर्शाने वाले उदाहरण है। पटेल की प्रासंगिकता इसी संतुलन में है कि दृढ़ता का अर्थ हठ नहीं और संवाद का अर्थ कमजोरी नहीं होती। कुशल नेतृत्व वही है, जो आवश्यक निर्णय लेने का साहस रखे, लेकिन निर्णयों के परिणामों और नागरिकों के हितों के प्रति भी सदैव सजग रहे। भारत का वर्तमान नेतृत्व सरदार पटेल के विचारों और नीति के अनुरूप अपने आपको साबित कर रहा है और आर्थिक विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन, सामाजिक न्याय और अवसरों का विस्तार, तकनीकी प्रगति के साथ नागरिक अधिकारों की रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसी चुनौतियों का समाधान कठोर निर्णयों के साथ तथ्यों की समझ, संवाद, संस्थागत क्षमता और दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर उन्हें यथार्थ में परिवर्तित कर रहा है।

गुजरात के एकता नगर में स्थापित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष की विश्व में सबसे सबसे ऊंची प्रतिमा'

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर सरदार वल्लभभाई पटेल की जयन्ती 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि देश की एकता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार और कर्तव्यबोध से जुड़ी हुई है। एकता दिवस सरदार पटेल के विचार को आगे बढ़ाने का अवसर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (182 मीटर) बना उस स्थल का नाम एकता नगर (पुराना नाम केवड़िया) रखा है। सरदार पटेल को समर्पित यह स्मारक देश-विदेश के करोड़ों लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है ।

राजस्थान के गठन पर ऐतिहासिक समारोह में शामिल हुए थे सरदार पटेल-राजस्थान विधान सभा की संविधान गैलेरी में है ऐतिहासिक चित्र

राजस्थान के गठन के ऐतिहासिक समारोह में स्वयं सरदार वल्लभभाई पटेल शामिल हुए थे। पिछले वर्षों में राजस्थान विधान सभा में किए जा रहें नवाचारों की श्रृंखला में विधान सभा के डिजिटल म्यूजियम में संविधान गैलेरी का निर्माण कर उसमें सरदार पटेल के सदप्रयासों से भारत और राजस्थान के एकीकरण की कहानी को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष कर 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभभाई पटेल की उपस्थिति में जयपुर में आयोजित राजस्थान राज्य के गठन के ऐतिहासिक समारोह के चित्रों को प्रमुखता के साथ गैलेरी में प्रदर्शित किया गया है । विधान सभा के संग्रहालय को जन-दर्शन के लिए खोलने के बाद अब तक 50,000 से भी अधिक लोग इसे देख चुके है।

एकता का अर्थ एकरूपता नहीं

भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता है। यहाँ भाषाएँ बदलती हैं, वेशभूषाएँ बदलती हैं, खानपान और लोकपरंपराएँ बदलती हैं, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भारत में एक साझा राष्ट्रीय पहचान विकसित हुई है। सरदार पटेल की विरासत हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ सभी भिन्नताओं को समाप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें एक व्यापक संवैधानिक और राष्ट्रीय ढाँचे में सम्मानपूर्वक स्थान देना है। आज भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं, सामाजिक असमानताओं, भाषायी संवेदनशीलताओं और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद की आवश्यकता एवं ऐसी परिस्थितियों में सरदार पटेल का दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि मतभेदों का समाधान टकराव से अधिक संवाद, पारस्परिक विश्वास और संवैधानिक मर्यादाओं के माध्यम से खोजा जा सकता है। एक मजबूत राष्ट्र वह नहीं, जहाँ सभी नागरिक एक जैसा सोचें; बल्कि वह है, जहाँ अलग-अलग विचार रखने वाले नागरिक साझा संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। पटेल की राष्ट्रीय एकता की विरासत को इसी व्यापक अर्थ में समझना जरूरी है।

आज के युवाओं के लिए सरदार पटेल का जीवन अनुशासन, संगठन, परिश्रम और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का पाठ है। उन्होंने यह दिखाया कि व्यक्तिगत प्रतिभा तभी व्यापक प्रभाव पैदा करती है, जब उसे सामूहिक उद्देश्य से जोड़ा जाए। उनकी ताक़त,क्षमताओं एवं विरासत को केवल प्रदर्शनों एवं नारों, समारोहों और प्रतिमाओं, तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। युवाओं की शक्ति का सदुपयोग और वास्तविक सम्मान तब होगा, जब युवा राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चल कर राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करेंगे । युवा अपनी शक्ति का सदुपयोग राष्ट्र के निर्माण और विकास में लगाये तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए समर्पित रहें ।

साथ ही वे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को महत्व दें, मतभेदों के बावजूद संवाद बनाए रखें, सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठकर काम करें और भारतीय सनातन संस्कृति को आत्मसात करते हुए अपने तकनीकी ज्ञान एवं पेशेवर दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। यहीं आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। युवाओं की वास्तविक शक्ति उनके निष्पक्ष, ईमानदार तथा जवाबदेह संचालन में निहित होती है।

विरासत का अर्थ : इतिहास से आगे की जिम्मेदारी

सरदार वल्लभभाई पटेल का ऐतिहासिक योगदान निर्विवाद रूप से भारत के राजनीतिक एकीकरण और प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत बनाने से जुड़ा हुआ है। लेकिन उनकी विरासत का वास्तविक अर्थ इससे भी आगे जाता है। वह हमें एक ऐसे भारत की कल्पना करने की प्रेरणा देता है, जहाँ राष्ट्रीय एकता के साथ सामाजिक सद्भाव, विकास के साथ न्याय और शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी समान रूप से महत्वपूर्ण है । पटेल को याद करने का सबसे सार्थक तरीका उनके व्यक्तित्व को किसी एक प्रतीक में सीमित करना नहीं, बल्कि उन सार्थक मूल्यों को वर्तमान जीवन में उतारना है, जिनके आधार पर उन्होंने राष्ट्र-निर्माण में योगदान दिया। इतिहास का सम्मान तभी सार्थक होता है, जब वह वर्तमान को बेहतर बनाने की प्रेरणा बने।

सरदार वल्लभभाई पटेल की राष्ट्रीय एकता, दृढ़ नेतृत्व, सुशासन, प्रशासनिक निष्पक्षता और विविधता के बीच सहमति बनाने की दृष्टि और नीतियाँ आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि भारत की एकता को मजबूत रखने, विभिन्न संस्थाओं को विश्वसनीय बनाने और विविधताओं के बीच साझा राष्ट्रीय उद्देश्य विकसित करने की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल भूगोल से नहीं बनता,वह विश्वास, कर्तव्य, संस्थाओं और सामूहिक संकल्प से निर्मित होता है।यही सरदार पटेल की स्थायी विरासत है और यही आधुनिक भारत के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश है । लौह पुरुष के प्रात: स्मरणीय व्यक्तित्व को सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि !!

(लेखक वासुदेव देवनानी राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष हैं)

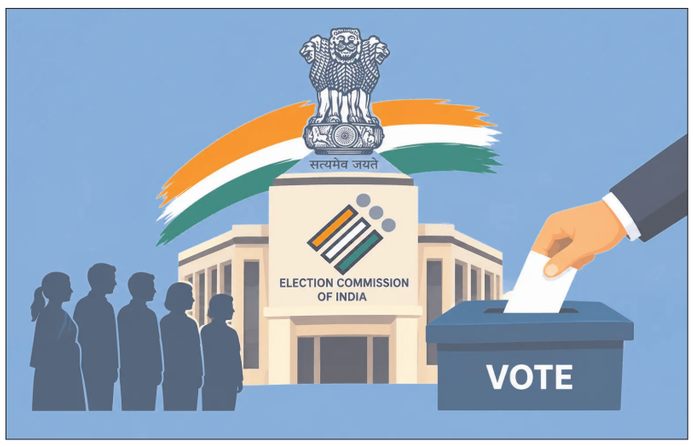
मतदाता सूची से नियुक्तियों तक सुधार की मांग, चुनाव आयोग के ढांचे पर उठे सवाल

भारत के लोकतंत्र की रक्षा केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाकर दूसरे को नियुक्त करने या हर विवादास्पद चुनावी फैसले को एक अलग राजनीतिक लड़ाई के रूप में चुनौती देने से नहीं हो सकती। विपक्ष को दो परस्पर पूरक सुधारों के लिए अभियान चलाना चाहिए। पहला, मतदाता सूचियों के रखरखाव और अद्यतन की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए, जबकि राष्ट्रीय मानक और निगरानी की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास रहे। दूसरा, निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार के निर्णायक प्रभाव को समाप्त किया जाए।

असल सुधार किसी एक अधिकारी को बदलने में नहीं, बल्कि उस संस्थागत व्यवस्था को बदलने में है जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) को लेकर चल रहा विरोध गलत मुद्दों पर केंद्रित है। विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले रहे हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्तों के विचारों की अनदेखी कर रहे हैं और मनमाने ढंग से मतदाता सूची से लोगों के नाम हटा रहे हैं।

इन चिंताओं की जांच की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष का आंदोलन दो बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटका रहा है। पहला, भारत का संविधान निर्वाचन आयोग को चुनावों के संबंध में व्यापक एकछत्र अधिकार देता है। दूसरा, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून शीर्ष अधिकारियों के चयन में केंद्र सरकार को निर्णायक अधिकार प्रदान करता है। यदि आलोचक वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, तो उन्हें एसआईआर और सीईसी को अलग-अलग समस्याओं के रूप में देखने के बजाय निर्वाचन आयोग से संबंधित कानूनों में बुनियादी सुधार की मांग करनी चाहिए। समस्या केवल यह नहीं है कि पद पर कौन बैठा है या किसी विशेष चुनावी प्रक्रिया को किस तरह संचालित किया जा रहा है। असली समस्या संस्थागत ढांचे में है, जो पूरी व्यवस्था को दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील बनाता है।

संविधान का अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को देता है। इतनी व्यापक शक्तियों का एक ही संस्था में केंद्रीकरण न तो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है और न ही भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए व्यावहारिक।



संयुक्त राज्य अमेरिका इसके विपरीत एक अलग मॉडल प्रस्तुत करता है। वहां राज्य और स्थानीय प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण संबंधी रिकॉर्ड का रखरखाव करते हैं और संघीय चुनावों सहित सभी चुनावों का संचालन करते हैं। यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था चुनावों के प्रशासन को किसी एक संस्था के हाथों में केंद्रित होने से रोकती है। साथ ही, यह व्यावहारिक वास्तविकता को स्वीकार करती है कि चुनावों का संचालन अंतत: स्थानीय स्तर पर ही होना है और स्थानीय प्राधिकरण इसके लिए अधिक सक्षम स्थिति में होते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी राज्य अपनी मनमानी कर सकते हैं। उन्हें संघीय चुनाव कानूनों का पालन करना पड़ता है। इनमें 1965 का वोटिंग राइट्स एक्ट, 1984 का वोटिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर दि एल्डरली एंड हैंडीकैप्ड एक्ट और 1993 का नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट शामिल हैं। ये कानून मतदान के अधिकारों की रक्षा करते हैं, भेदभाव पर रोक लगाते हैं, मतदाता पंजीकरण और मतदाता पहचान-पत्रों से संबंधित आवश्यकताएं निर्धारित करते हैं तथा मतदान केंद्रों तक पहुंच के लिए सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराते हैं। चुनावी चंदे और अभियान वित्त को नियंत्रित करने के लिए भी अलग कानून हैं।

हाल के वर्षों में अमेरिका में भी मतदाता सूचियां राज्य सरकारों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का विषय बनी हैं। मई 2025 से ट्रंप प्रशासन ने राज्यों के मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड तक पहुंच की मांग की है। उसका तर्क है कि संघीय कानून उसे रिकॉर्ड की शुद्धता की जांच के लिए उनका निरीक्षण करने का अधिकार देता है। कई राज्यों ने इसका विरोध किया और केंद्र सरकार के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाए। इसके परिणामस्वरूप 30 से अधिक मुकदमे दायर हुए, जिनमें से अधिकांश को अदालतों ने खारिज कर दिया।

भारत के विपक्ष के लिए इससे यह सबक मिलता है कि मतदाता सूची के प्रबंधन को एकमात्र राष्ट्रीय प्राधिकरण के हाथों में रखना जरूरी नहीं है। उसे ऐसे कानून की मांग करनी चाहिए, जिसके तहत मतदाता सूचियों के रखरखाव और उन्हें अद्यतन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी जाए, जबकि निर्वाचन आयोग को नियमित और स्वतंत्र ऑडिट कराने का अधिकार प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था अचानक बड़े पैमाने पर और व्यवधान पैदा करने वाले पुनरीक्षण अभियानों की आवश्यकता को कम कर सकती है। विपक्ष को एसआईआर को लेकर जनता में पैदा हुए असंतोष का इस्तेमाल इस बुनियादी सुधार के लिए दबाव बनाने में करना चाहिए। अन्यथा, एसआईआर को पूरी तरह रोकने की उसकी मांग का ठोस कानूनी आधार कमजोर दिखाई देता है। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण एक वैध जिम्मेदारी है, वास्तविक सवाल यह है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और पर्याप्त सुरक्षा उपायों से युक्त है या नहीं। पुनरीक्षण को पूरी तरह रोकने की मांग उतनी ही मनमानी प्रतीत होती है, जितने मनमाने फैसलों का आरोप विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर लगा रहा है।

दूसरी बुनियादी समस्या उन अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ी है, जो चुनावों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। कई दशकों तक नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रही, क्योंकि संसद ने लंबे समय तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया था, जो स्वतंत्र चयन तंत्र निर्धारित करता। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक संसद ऐसा कानून नहीं बनाती, तब तक नियुक्तियों की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद संसद ने एक नया कानून बनाया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को शामिल किया गया। अब चयन समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। इस प्रकार सरकार के पास समिति के तीन में से दो सदस्यों का समर्थन होता है। यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से हितों के टकराव की स्थिति पैदा करती है। इससे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को लेकर विश्वास कमजोर होता है, भले ही नियुक्त किया गया कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निष्पक्ष तरीके से काम करे।

2023 का यह कानून विपक्ष के कड़े विरोध के बीच पारित हुआ था। सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया, जहां विपक्षी सदस्यों के सदन से बहिर्गमन के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

इसके कुछ दिन बाद लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया। उस समय संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़े पैमाने पर विपक्षी सांसदों के निलंबन के कारण अधिकांश विपक्षी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। उस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों के कुल 146 विपक्षी सांसद निलंबित किए गए थे। अब विपक्ष को वास्तव में स्वतंत्र चयन तंत्र की मांग करनी चाहिए, जिसमें सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधियों के साथ-साथ न्यायपालिका और अन्य विश्वसनीय संवैधानिक या सार्वजनिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हों। प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी एक राजनीतिक दल को परिणाम तय करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

क्यों होता है त्वचा में ढीलापन और कैसे पायें इससे निजात



उम्र कई तरीके से अपना असर छोड़ती है। उम्र का असर आपकी त्वचा पर नजर आ ही जाता है। आपकी खूबसूरत दमकमी त्वचा का कसाव कम हो जाता है। हालांकि उम्र त्वचा के ढीलेपन की एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ अन्य कारक भी हो सकते हैं। त्वचा का ढीलापन दूर करने के लिए उसके सही कारण का पता होना जरूरी है। तभी आप इससे कारगर तरीके से निपट सकते हैं। हालांकि, आप यही सोच रहे होंगे कि त्वचा के इस ढीलेपन को दूर करना बहुत मुश्किल काम है, तो कुछ ऐसे रास्ते हैं, जिन्हें अपनाकर आप त्वचा के ढीलेपन के लक्षणों से लड़ सकते हैं।

उम्र :

त्वचा के ढीलेपन का यह सबसे सामान्य कारण है। लेकिन, कई बार जवानी में भी त्वचा अपना प्राकृतिक कसाव खो देती है। उम्र और सूर्य की हानिकारक किरणों का मेल त्वचा के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। इसके कारण त्वचा का कसाव कम होने लगता है और वह ढीली होने लगती है। समुद्री घास आपके काफी काम आ सकती है। आप इसे एक मुखौटे की तरह अपने पूरे शरीर पर लपेट लें। और अगर आप इसके लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लेते हैं, तो इसके ऊपर आपको एक गर्म कम्बल ओढ़ा दिया जाएगा। इससे उस घास में गर्मी पैदा होगी, जो आपकी त्वचा में कसाव पैदा करने में मदद करेगी। आपको अपनी त्वचा में कसाव हासिल करने में जल्दी नहीं मचानी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस उम्र में आपकी त्वचा में पहले जैसा लचीलापन नहीं रहता।

वजन कम करें:

मोटापे के शिकार लोगों के साथ इस तरह की समस्या आम होती है। उनके शरीर पर काफी अतिरिक्त चर्बी होती है। ऐसे लोगों को त्वचा के ढीलेपन की शिकायत अक्सर किसी बड़े ऑपरेशन के बाद अथवा बेतरतीब तरीके से की गयी डायटिंग के बाद उन्हें त्वचा सम्बन्धी ये परेशानियां नजर आने लगती हैं। अतिरिक्त वजन कम करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सही तरीका आजमाना भी जरूरी है। अगर नियमों का पालन सही तरीके न किया जाए, तो इससे सेहत को तो नुकसान होता ही है साथ ही त्वचा में भी ढीलापन आ जाता है।

धूप में निकलने से पहले:

अगर आप नियमित तौर पर लम्बे वक्त के लिए धूप में रहते हैं, तो उसका असर आपकी त्वचा पर पड़ता है। धूप में अधिक देर तक रहने का असर भले ही आपको जवानी में नजर न आए, लेकिन उम्र के एक खास पड़ाव पर आकर वह जरूर नजर आता है। सूरज की किरणों से स्किन कैंसर होने का खतरा भी होता है। इससे बचने के लिए धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और त्वचा पर एक्सट्रा माश्चराइजर लगाएं।

कमजोर मांसपेशियां:

अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं, तो इसका असर आपकी त्वचा पर भी पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इससे आपकी त्वचा ढीली हो जाएगी। इससे बचने के लिए अपनी मांसपेशियों को मजबूत और सही आकार में रखने का प्रयास करें। इसके लिए आपको सप्ताह में पांच बार मांसपेशियों का व्यायाम किया जाए। आपको अपनी बाहों की निचली त्वचा को टाइट रखने के लिए हल्के वजन के साथ व्यायाम करना चाहिए।

घर कहेगा तुम्हारा स्वागत है!

घर हमारी परछाई है। जैसे हम, वैसा ही हमारा घर। त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है, साथ ही शुरू हो चुका है घर की साफ-सफाई और सजावट का दौर भी। त्योहारों के मौसम में अपने घर को आसानी से कैसे सजाएं, बता रही हैं शाश्वती त्योहारों के मौसम में घर की साफ-सफाई करना और पेंटिंग करवाना आम बात है। पर मुख्य सवाल तो यह है कि ज्यादा पैसा खर्च किए बिना घर को त्योहारी लुक कैसे दिया जाए? त्योहार के मौसम में हम सब की कोशिश होती है कि हम अपने घर को पारंपरिक लुक दें। इस बात को ध्यान में रखते हुए घर की साफ-सफाई के दौरान ऐसा जो भी सामान आपको नजर आए, जिसका इस्तेमाल घर की सजावट में हो सकता है, जैसे सजावटी दीया या फिर कोई खूबसूरत वॉल पेपर आदि उन्हें एक ओर रखती जाएं। जब त्योहारों के लिए घर की सजावट शुरू करें तो इन सामान को इस्तेमाल में लाएं। घर में पहले से जो सामान उपलब्ध हैं, उनका नए तरीके से सजावट में इस्तेमाल करें।गणपति विघ्नहर्ता हैं, शुभ कार्यों के प्रतीक हैं और परोपकारी हैं। गणपति की मूर्ति का इस्तेमाल आप अपने घर को फेस्टिव लुक देने के लिए कर सकती हैं। गणपति की मूर्ति को अपने घर के किसी ऐसे हिस्से में रखें, जहां सबकी नजर जाए। मूर्ति को खूबसूरत फूलों से सजा दें। आप चाहें तो गणपति के अलग-अलग रूपों की छोटी-छोटी मूर्तियों को अपने घर के किसी एक हिस्से में सजा सकती हैं। चाहें तो अलग-अलग भगवान-भगवती की छोटी-छोटी मूर्तियों को एक जगह रखें और उसके आसपास गुलाब की पंखुडियां बिखेर कर एक दीप वहां जला दें। ज्यादा मेहनत के बिना ही आपके घर को एक अनोखा त्योहारी लुक मिल जाएगा। घर की सजावट में अगर सिल्क या ब्रोकेड का इस्तेमाल किया जाए तो घर का माहौल अपने-आप त्योहारी हो जाता है। घर की सजावट के लिए आपको खासतौर पर सिल्क या ब्रोकेड के कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। घर की इस सजावट में आपका वॉर्डरोब आपकी मदद कर देगा। अपने वॉर्डरोब से बनारसी सिल्क साड़ी, बांधनी दुपट्टा या फिर सिल्क स्टोल निकालें और उनका इस्तेमाल घर की सजावट में करें। गुलाबी, बैंगनी जैसे रंगों वाले कपड़े चुनें और इन्हें परदे आदि पर लपेट दें। आप अपने सोफा पर सिल्क की साड़ी को लपेटकर अंत में एक खूबसूरत-सी गांठ भी बांध सकती हैं। अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करें और नारंगी, गुलाबी, लाल या हरे रंग की एक्सेसरीज का इस्तेमाल घर की सजावट में करें। आपके घर में अगर पीतल का बना सजावट का कोई समान है तो उसे त्योहारों से कुछ दिन पहले निकालकर उस पर पॉलिश करवा दें। अगर पीतल की कोई गहरी थाली है तो उसमें पानी भरकर उसमें कुछ खूबसूरत फूल डाल सकती हैं। तांबे से बना दीप, घंटी या पूजा-पाठ के अन्य सामान का सजावट में इस्तेमाल कर आप अपने घर को त्योहारी लुक दे सकती हैं।घर को त्योहारी लुक देने में ताजे फूल भी आपका साथ दे सकते हैं।





घर की सजावट में अगर सिल्क या ब्रोकेड का इस्तेमाल किया जाए तो घर का माहौल अपने-आप त्योहारी हो जाता है। घर की सजावट के लिए आपको खासतौर पर सिल्क या ब्रोकेड के कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। घर की इस सजावट में आपका वॉर्डरोब आपकी मदद कर देगा। अपने वॉर्डरोब से बनारसी सिल्क साड़ी, बांधनी दुपट्टा या फिर सिल्क स्टोल निकालें और उनका इस्तेमाल घर की सजावट में करें। गुलाबी, बैंगनी जैसे रंगों वाले कपड़े चुनें और इन्हें परदे आदि पर लपेट दें।

ताकि आपका रिश्ता हंसे-खिलखिलाए

कई बार हमारी कोई आदत हमारे साथ रहने वालों पर भारी पड़ रही होती है और हमें पता भी नहीं होता। समय रहते ऐसी आदतों से बाज आ जाएं, ताकि रिश्ते की गाड़ी पटरी पर ही बनी रहे। रिश्तों को कैसे रखें खुशहाल,रोमांटिक उपन्यासों की प्रसिद्ध लेखिका बार्बरा वाइट ने अपनी आत्मकथा में अपने पति के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए लिखा था, 'मैं अपने पति को बहुत चाहती थी और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, पर शादी के बीस साल बाद जब एक दिन उन्होंने कहा कि वह मुझसे तलाक लेना चाहते हैं तो मुझे गहरा धक्का लगा। मेरी समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या किया है, जिससे बात तलाक तक आ पहुंची है।' बार्बरा दो साल तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाईं। जब थोड़ी सामान्य हुईं तो अपने पति से जानना चाहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पति ने जवाब दिया कि तुम्हारे दिन में सोने और रात भर जग कर लिखने की आदत से मैं परेशान रहता था। पर मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम एक प्रसिद्ध लेखिका थीं और मेरे कुछ कहने पर यह जवाब दे सकती थीं कि मैं स्त्री विरोधी हूं। पर बार्बरा ने बताया कि अगर उनके पति ने एक बार भी उनकी इस आदत पर आपत्ति जताई होती तो वे रात में जाग कर लिखने की आदत छोड़ देतीं।ऐसी कई छोटी-बड़ी आदतें होती हैं, जिससे साथ रहने वाला दूसरा व्यक्ति परेशान हो सकता है। मनोचिकित्सक डॉक्टर रत्ना बाली के अनुसार, 'शादी की शुरुआत में पति-पत्नी दोनों एक दूसरे की आदतों को नजरअंदाज करते हैं, पर बाद में यही झगड़े की बहुत बड़ी वजह बन जाती हैं। मेरे पास कुछ दिनों पहले राजवीर आए थे, वे चाहते थे कि मैं उनकी पत्नी मानसी का इलाज करूं। शादी के बाद उनकी पत्नी को उनके घर के किसी भी कोने में सिगरेट पीने पर आपत्ति नहीं थी, पर पिछले दो सालों से राजवीर जैसे ही घर के अंदर सिगरेट पीना शुरू करते थे, मानसी झगड़ने लगती थी।' ऐसा कैसे हो गया कि पति की जिस आदत से पत्नी दो सालों तक परेशान नहीं रही, अब उसी आदत की वजह से रोज घर में झगड़ा होने लगा है? रत्ना कहती हैं, 'आप जब किसी से नया रिश्ता जोड़ते हैं तो उस समय आप हर कीमत पर उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं और हर तरह का समझौता करते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है, जब आपको अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है और तब आपकी प्रतिक्रिया बेहद तीखी हो सकती है।'पति-पत्नी एक दूसरे की हर आदत को सलाम करें, ऐसा कम ही होता है। अगर बातों-बातों में दोनों को यह पता चल जाए कि उनकी कौन-सी बात उनके जीवनसाथी को परेशान कर रही है तो वक्त रहते उस पर काबू पाया जा सकता है। घर में रोज-रोज के झगड़े-तनावों से बचने के लिए अगर पति-पत्नी खुल कर एक-दूसरे को अपनी पसंद-नापसंद बता दें तो बिगड़ी बात काफी हद तक बन जाती है।

पत्नियां भी कम नहीं- अधिकांश पति अपनी पत्नी के चटोरेपन की आदत से परेशान रहते हैं।

गाड़ी चलाते समय पत्नियों की टोकाटोकी पति पसंद नहीं करते।

हर समय यह कहना कि क्या पहनें, इससे पति घबराते हैं।

पत्नियों की बेवजह खरीदारी की आदत से भी पति तनाव में आ जाते हैं।

पत्नी को नहीं भाती ये आदतें

पति का हर समय स्पोर्ट्स चैनल देखना।

छुट्टी के दिन न नहाना।

रास्ता भटकने पर किसी से पता ना पूछना।

पैर और हाथ के नाखून घर के अंदर काटना।

भीगा तौलिया बिस्तर पर डालना।

त्योहारों पर भाने लगीं रंग-बिरंगी साड़ियां

त्योहारों का मौसम आ गया हैं। महिलाओं की शॉपिंग भी शुरू हो गई है। दिवाली, भाइदूज, और छठ जैसे त्योहार के लिए नए कपड़े, गहने, गैजेट और उपहार खरीदे जाते हैं। भारत की पारम्परिक साड़ियां और महिलाओं का श्रृंगार पूरे विश्व में सबसे खास और अलग हैं।

भारतीय परिधानों की तो दुनिया भर की महिलाओं दीवानी हैं। पहले साड़ियां बेहद सिंपल होती थी। साड़ी पर बनने वाले डिजाइन पेड़, पौधे, मनुष्य वगैरह के होते थे। सूती और रेशम की साड़ियां ही ज्यादातर महिलाओं की फेवरेट हुआ करती थीं। मगर धीरे-धीरे साड़ियों के डिजाइन और कपड़े को लेकर भी काफी बदलाव किए गए। अब तो जमाना कॉकटेल साड़ियों का है। दो-तीन रंग की साड़ियां और उसके पल्लू और बार्डर या फिर पूरी साड़ी पर बेहतरीन कारीगरी होती है।

त्योहारों से लेकर शादी-ब्याह तक में साड़ी का प्रचलन रहता हैं। बनारस की बनारसी साड़ियां, ओड़िशा की सूती और रेशमी साड़ी, तमिलनाडु की कांजीवरम, बंगाल की बालुचरी, मैसूर की सिल्क साड़ी, राजस्थान की बांधनी, गुजरात की बंधेज और सबसे खूबसूरत लखनऊ की चिकन कढ़ाई की साडियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।आधुनिक दौर में भी साड़ियों का महत्व कम नहीं हुआ। अब वे नए रूप में लुभाने आ गई हैं। शादी-ब्याह में दुल्हन अब लहंगा-चोली पहनना पसंद करती हैं। मगर आज अलग दिखने की चाह में युवतियां भी साड़ी ही पहनना चाहती हैं। तीज, करवा चौथ और दिवाली जैसे मौके पर तो साड़ी पहनना महिलाओं की पहली पसंद होती हैं। उसमें वे बेहद खूबसूरत और शालीन दिखती हैं। हसबैंड भी पत्नी को साड़ी में देखकर अब खुश होते हैं।वैसे साड़ियां भी अब मार्डन हो गई हैं, डिजाइनर साडियां ज्यादा फैशनेबल और हल्की हो गई हैं। परदे पर दिखने वाली अभिनेत्रियों की पसंदीदा साड़ियां अब आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं।

आज कॉकटेल साड़ियां युवतियों और महिलाओं की पहली पसंद बन रही हैं। बड़े डिजाइनरों द्वारा तैयार ये साड़ियां अब मार्केट में आसानी से दिखने लगी हैं। दो रंगों को मिलाकर बनी ये साड़ियां महिलाओं की सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। हैवी वर्क के साथ बनी ये साड़ियां बेहतरीन लुक देती हैं। पार्टी वियर के साथ-साथ यह त्योहारों में भी चार चांद लगा देती हैं।

पहले जहां फ्लोरल प्रिंट की साड़ियां पसंद की जाती थीं वहीं अब एनिमल प्रिंट, प्राकृतिक दृश्यों की प्रिंट वाली साड़ियां चलन में आ रही हैं। अब तो नेट साड़ियों का ट्रेंड भी बढ़ रहा हैं। साथ ही रेडी टू वियर साड़ियां भी ट्रेंड में हैं।

रंगों की बात करें, तो त्योहारों पर चटख रंग ज्यादा पसंद किए जाते हैं। जैसे मरून, ब्लू, आरेंज और पिंक।

तो अब आने वाले त्योहारों पर अगर आप भी कुछ अलग दिखना चाहती हैं, तो डिजाइनर साड़ियां कैरी करें।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा को संबोधित किया

कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटा, अब लोकतंत्र के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है- शर्मा







जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कोटा में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा को संबोधित किया और इसके पश्चात पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिन लोगों ने कभी लोकतंत्र को माना ही नहीं और संविधान को हमेशा तोड़ने का काम किया, वे आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र जनता की शक्ति है और देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा का आधार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की गौरवशाली विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों का डंका बज रहा है। दुनिया ने माना है कि प्रजातंत्र सही मायने में अगर जीवंत और सशक्त है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना और अपनी बात रखना सबका अधिकार है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति का दोहरापन देखिए कि जब चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है और जब परिणाम पक्ष में नहीं आते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के सारे आंकड़े तोड़ दिए और लोकतंत्र का मजाक बनाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। जहां ये जीतते हैं वहां इनके लिए ईवीएम सही और जहां हारते हैं वहां खराब है, ऐसा इनका दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 के आपातकाल के समय कांग्रेस ने लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंट दिया गया था और संविधान की मर्यादा को कुचला था। जिसकी वजह से अनेक लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों ने असहनीय पीड़ा झेली। उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि क्या आपातकाल व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर नहीं लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के काले दौर से सबक लेते हुए हम सभी को देश के लोकतंत्र, इसकी पवित्र संस्थाओं और संविधान की रक्षा के लिए सदैव डटे रहने का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार में रहते हुए राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया था, यह बात उसे याद रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश के गौरव एवं स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए। सेना, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा और अगर खाया है, तो उसको भी निकाल लूंगा। जबकि कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद के आधार पर काम किया और जनता के दर्द को कभी नहीं जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता दिन के 24 घंटे, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन जनता के बीच रहकर काम करता है। भाजपा ने लंबे समय तक विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाई। हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर उनकी संवेदनाओं में शामिल होकर देश की जनता का दिल जीता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जब सरकार में होते हैं तो चार-चार महीने होटलों में बिता देते हैं। इनके लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता देश में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं।

मुख्यमंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तविक मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहें और अपात्र प्रविष्टियों की नियमानुसार जांच हो, ये दोनों बातें आवश्यक हैं। यदि किसी को एसआईआर की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो उसे ठोस प्रमाणों के साथ सक्षम प्राधिकरण और न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में एसआईआर से संबंधित विभिन्न आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर से संबंधित प्रमुख आदेश सर्वसम्मति से अनुमोदित किए गए थे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार वैधानिक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राजस्थान में सत्ता संघर्ष के दौरान चार महीने तक कांग्रेस होटलों में बंद थी। इनकी सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव कराने में दो साल लगाए। हर तीन महीने में आचार संहिता लगाते थे। उन्होंने कहा कि हमने वन स्टेट-वन इलेक्शन की बात कही तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये नहीं करा पाएंगे, तुम्हारे काका जी भी नहीं करा पाएंगे। अब वो देख लें कि काका जी ने चुनाव कराए कि नहीं। निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इनके शासनकाल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का किस तरह दुरुपयोग किया, यह जनता जानती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अब तक 265 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और करीब 700 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। कई मामलों में शत-प्रतिशत पेंशन रोकी गई है तथा कार्मिकों को सेवा से हटाने और बर्खास्त करने जैसी कार्रवाई भी की गई है।

शिखर अग्रवाल प्रकरण में मुख्यमंत्री जवाब दें, सीबीआई या ईडी से हो जांच- गहलोत

जयपुर (कासं)। कांग्रेस एवं INDIA गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली के महत्व और देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की।



श्रीमती इंदिरा गांधी के समय की ऐतिहासिक रैली को याद करते हुए गहलोत ने कहा कि वर्ष 1978-79 में जब श्रीमती गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं, तब 'भारत बचाओ' रैली आयोजित हुई थी। उस रैली के बाद पूरे देश में एक संदेश गया और इंदिरा जी के पक्ष में ऐसी आंधी चली कि जनता पार्टी की सरकार को जाना पड़ा। कांग्रेस भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीती और उन्हें भी पहली बार सांसद बनने का सौभाग्य मिला। उस आंदोलन को वर्तमान हालात से जोड़ते हुए गहलोत ने कहा कि आज एक बार फिर देश के सामने लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है। देश के हालात से आमजन में गहरा आक्रोश और चिंता है। ऐसे में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली का विशेष महत्व है। उन्होंने सभी कांग्रेसजनों और आम नागरिकों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचकर रैली में भाग लें। भले ही अपने साधनों से जाना पड़े, लेकिन सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। इससे देशभर में एक संदेश जाएगा और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की रैलियों को लेकर जानबूझकर यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन अराजकता फैला रहे हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी और रैलियां करती थी, तब वह जनता के हितों की बात करती थी। आज विपक्ष रैली कर रहा है तो उसे अराजकता फैलाने वाला बताया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के प्राचार्यों से संवाद

जनजातीय आवासीय विद्यालयों में नवाचारों एवं बेहतर कार्यप्रणालियों को बढ़ावा दें- मुख्य सचिव

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के कौशल विकास एवं सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के प्राचार्यों से संवाद किया। इस दौरान एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल प्रेमनगर, राजकीय मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल ढिकली, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मल्लाना , बहुउद्देशीय छात्रावास कोटा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कुशलगढ़,



एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खेरवाड़ा, राजकीय मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरपुर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिहारीपुरा, राजकीय जनजाति बालिका बहुउद्देशीय छात्रावास बारां तथा कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड के प्राचार्यों एवं प्रतिनिधियों ने अपने-अपने संस्थानों की उपलब्धियों, आधारभूत संरचना, परीक्षा परिणामों एवं शैक्षणिक गतिविधियों का पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव ने इन विद्यालयों की उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, बेहतर शैक्षणिक परिणामों एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में सभी प्राचार्य प्रत्येक माह आपसी बैठक आयोजित कर अपने-अपने विद्यालयों में किए जा रहे नवाचारों, उपलब्धियों एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करें, ताकि एक विद्यालय में अपनाई जा रही अच्छी पहल को अन्य विद्यालयों में भी लागू किया जा सके। मुख्य सचिव ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मल्लाना, अलवर द्वारा शुरू की गई न्यूजलेटर की पहल की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि अन्य विद्यालय भी इस पहल से प्रेरणा लेकर अपने यहां प्रतिमाह न्यूजलेटर प्रकाशित करें। इसमें विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों, नवाचारों एवं विशेष आयोजनों को प्रमुखता से शामिल किया जाए।

'नशामुक्त भारत' महायज्ञ बने हम सभी का संकल्प- राज्यपाल



जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि यज्ञ त्याग, समर्पण, और अर्पण से जुड़ा होता है। वैदिक परंपरा में यज्ञ केवल अग्नि में घी और मंत्रों की आहुति देने तक सीमित नहीं है। समाज का कल्याण, परोपकार, सत्य और श्रेष्ठ कर्म भी यज्ञ कहलाते हैं। उन्होंने नए भारत के निर्माण में 'नशामुक्त भारत' संकल्प यज्ञ में सभी को मिलकर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। बागडे शुक्रवार को भारत विकास परिषद एवं आर्य युवा समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 501 कुण्डीय संस्कार महायज्ञ नशामुक्त भारत संकल्प कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 501 कुंडीय महायज्ञ में आहुति भी दी।

महर्षि अरविंद के लिखे 'वेद रहस्य' की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यज्ञ सत्य, प्रकाश और अमरत्व की खोज है। यह महायज्ञ भी जीवन की सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला है। राज्यपाल ने देश के स्कूल, कॉलेज के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताते हुए कहा कि पड़ोसी देश नहीं चाहते की भारत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत देश के युवाओं और यहां के लोगों के भरोसे से ही आगे बढ़ रहा है। इसीलिए पड़ोसी देश मादक पदार्थ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि देश को कमजोर करने के लिए बाहर से भेजते हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 'नशामुक्त भारत' कार्यक्रम इसीलिए चलाया है कि देश पड़ोसी देशों के षडयंत्र का शिकार नहीं हो। उन्होंने कहा कि नया भारत इस तरह राष्ट्र को कमजोर करने वाले कारणों के खिलाफ कार्य करने वाला है। उन्होंने कहा कि नया भारत आत्म निर्भरता के लिए स्वदेशी उत्पादों का निर्माण वाला है। नया भारत अर्थव्यवस्था में विश्वभर में तेजी से आगे बढ़ने वाला है।

राज्यपाल ने ली विश्वविद्यालयों की विशेष समीक्षा बैठक

उद्यम-एकेडमिक समन्वय करते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता के केंद्र बनाए-राज्यपाल

जयपुर (कासं)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचारों को बढ़ावा देते हुए उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कोर्स विकसित करते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता के केंद्र बनाए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं को पाठ्यपुस्तकों के अलावा विषय विशेषज्ञों के ऑनलाइन व्याख्यान करवाने और कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों के क्रियान्वयन की भी आवश्यकता जताई।

बागडे शुक्रवार को लोकभवन में प्रदेश के वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की विशेष समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत भवन निर्माण और मरम्मत कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाना सुनिश्चित किए जाने के भी विशेष रूप से बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण एजेंसियों की समीक्षा करने और सम्बद्ध अधिकारियों को कार्यों का मौके पर नियमित भौतिक निरीक्षण किए जाने की भी हिदायत दी। उन्होंने राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को इस संबंध में प्रदत अनुदान राशि का समुचित उपयोग किए जाने के साथ ही इससे जुड़ी कार्य एजेंसियों के कार्य का प्रमाणन गुणवता के आधार पर किए जाने पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में यह जरूरी है कि हमारे विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। इसके लिए वहां ज्ञान के सभी अनुशासनों में विषय विशेषज्ञों का ऑनलाइन व्याख्यान करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विषय विशेष से जुड़े देश विदेश के विशिष्टजनों को चिन्हित



कर उनकी ऑनलाइन सेवाएं पढ़ाने के लिए भी ली जाए। इसके बहुत अच्छे दूरगामी सकारात्मक प्रभाव उच्च शिक्षा में मिलेंगे।

बागडे ने कहा कि विश्वविद्यालय उद्योगों की आवश्यकता के बारे में समय समय पर जानकारियां ले और उनके अनुरूप अपने यहां कोर्स ही विकसित नहीं करें बल्कि कौशल विकास से भी विद्यार्थियों को जोड़े ताकि उनकी आवश्यकतानुसार मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। उन्होंने नीमराना स्थित रैफल्स यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हुए कहा कि वहां उद्योगों की मांग के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है। इस मॉडल पर हमारे विश्वविद्यालय कार्य करें। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के मानदंडों के अनुरूप कार्य करने और इस संबंध में प्रदत राशि का निर्माण कार्यों में पारदर्शिता से उपयोग किए जाने पर जोर दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ाए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी सम्बन्ध में प्रदेश में 25 प्रतिशत नामांकन वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले दो वर्षों में 76 नए कॉलेज खोले गए हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर को ऐसा हब बनाया गया है जहां विभिन्न अनुशासनों के विश्वविद्यालयों का समन्वय है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त को लीफ आर्टिस्ट खेतेश गोयल ने लीफ आर्ट भेंट किया



बाड़मेर/जयपुर (कासं)। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के बाड़मेर प्रवास के दौरान लीफ आर्टिस्ट खेतेश गोयल ने पीपल के पत्ते पर स्वीप के लोगो की आकृति उकेरकर उसकी तस्वीर राज्य निर्वाचन आयुक्त को सौंपी। इसके जरिए प्रदेश की जनता से पंचायती राज चुनावों में बढ़-चढ़कर मतदान करने एवं पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की गई है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल को मतदाता जागरूकता का संदेश देने वाली तस्वीर भेंट की गई। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने लीफ आर्टिस्ट खेतेश गोयल से उनकी कला के बारे में विस्तार से जानकारी ली और इस अनूठे प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वीप अभियान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के नवीन एवं आकर्षक तरीकों की क्रियान्विति अभिनव पहल है। गोयल ने बताया कि वर्तमान में वह जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करते हुए लीफ आर्ट सीखना शुरू किया।

इसके बाद से वह समय-समय पर अपनी कलाकृतियों के माध्यम से विभिन्न जागरूकता अभियानों में भागीदारी निभाते रहते है।

न्यूज इनबॉक्स

जयपुर पुलिस कमिश्नर की अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई

आदेश के बावजूद भी नहीं पहुंचे चुनाव ड्यूटी पर, 4 कांस्टेबलों की सेवा समाप्त

जयपुर (कासं)। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। बिना आधिकारिक अनुमति के लंबे समय से अनुपस्थित और निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी पर आदेश के बाद भी गैरहाजिर रहने पर 4 कांस्टेबल (प्रशिक्षु) को सेवा से पृथक किया गया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि पुलिस बल में अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इलेक्शन जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी पर भी नहीं आना अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। किसी भी कार्मिक की अनधिकृत गैरहाजिरी से ड्यूटी व्यवस्था के साथ-साथ पुलिस फोर्स के अनुशासन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए 4 कांस्टेबल (प्रशिक्षु) को सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए । इस संबंध में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) श्रीमती अनुष्ठा कालिया ने आदेश जारी किए हैं। सेवा से पृथक होने वाले रिक्रूट कांस्टेबलों में लोकेश कश्यप रि. कानि.-10033, विजय सिंह रि. कानि 4049, मोहरी लाल रि. 7997, बजरंग लाल रि. कानि 7346 शामिल हैं।

सिविल एवं पारिवारिक पेंशनर्स 30 नवम्बर तक प्रस्तुत करें जीवन प्रमाण पत्र

जयपुर (कासं)। राजस्थान सरकार के समस्त सिविल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को माह नवम्बर, 2026 में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र 30 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 के अनुसार प्रत्येक पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए प्रतिवर्ष माह नवम्बर में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए ड्डस्रस्र 3.0 पर कर्मचारी की स्वयं की स्स्ह्र ड्ढह्र के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाणन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित कोषालय/उप कोषालय अथवा निदेशालय पेंशन एवं संभागीय पेंशन कार्यालयों की हेल्पडेस्क पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी जीवन प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान सरकार के समस्त सिविल एवं पारिवारिक पेंशनर्स से अपील है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अर्थात 30 नवम्बर, 2026 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नवम्बर, 2026 की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर-2, जयपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जयपुर (कासं)। सड़क सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने तथा यातायात नियमों के पालन की महत्ता समझाने के उद्देश्य से आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर-2, आर्मी मुख्यालय, झोटवाड़ा, जयपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिनेश सिंह, परिवहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर द्वितीय, विद्याधर नगर, ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर रोड सेफ्टी एनजीओ कम्युनिटी फॉर सेफर रोड्स की प्रतिनिधि श्रीमती निशा बग्गा तथा विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रदीप कुमार टेलर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को यातायात नियमों, सड़क संकेतकों, सड़क चिह्नांकन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, पैदल यात्रियों की सुरक्षा तथा सुरक्षित सड़क व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई। दिनेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क सुरक्षा केवल यातायात नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। थोड़ी-सी सावधानी, यातायात नियमों का पालन और अनुशासित व्यवहार बहुमूल्य जीवन को बचा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।

आरएसजीएल के अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के अधिकारयों व कार्मिकों ने सतर्कता जागरुकता सप्ताह के अवसर पर राष्ट्र की एकता, अंखड़ता और सत्यनिष्ठा की शपथ ली। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने अधिकारियों व कार्मिकों को एकता, अंखडता और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार मुक्त व सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई। सतर्कता जागरुकता सप्ताह की इस साल की थीम सत्यनिष्ठा से समृद्धि रखा गया है। विनय पाटनी ने कोटा, नीमराणा, कूकस व ग्वालियर-श्योपुर के अधिकारियों व कार्मिकों को वर्चुअली शपथ दिलाई। एमडी विनय पाटनी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी देशवासियों को भागीदारी आवश्यक है वहीं जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों की पालना का संकल्प और पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का अंग बनना चाहिए। उपमहाप्रबंधक सीएनपी विवेक श्रीवास्तव ने इस अवसर पर जारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संदेश, सीएफओ दीप्तांशु पारीक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डीजीएम कोटा सीपी चौधरी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण् और उपप्रबंधक आईटी गगनदीप राजोरिया ने सीवीसी के संदेश का वाचन किया।

सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ निगम सख्त, 5 कैंटर सामान गोदाम पहुंचाया

जयपुर। नगर निगम जयपुर आयुक्त ओम कसेरा के निर्देषानुसार एवं पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में शुक्रवार को सतर्कता शाखा की द्वारा नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में एमएलए क्वार्टर लालकोठी, बजाज नगर, कैलाष टावर, एयरपोर्ट रोड़, वीटी रोड़ स्वर्णपथ एवं अरावली मार्ग से अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 2 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 05 केन्टर सामान जब्त किया गया।

Jiont Director Bikaner
Swasthya Bhawan Bikaner

Date: 25.10.2026

NOTICE INVITING BIDS
UBN: Services/2026-27/0074/058

Bids for Procurement of Boarding and lodging are invited from interested bidders up to 04.11.2026 06:00PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://shpp.rajasthan.gov.in) of the state, and respective department's website. The approximate value of procurement is INR 9,90,000.00
Thanking you.
Yours faithfully,

DR DEVENDRA KUMAR CHAUDHARY
JOINT DIRECTOR
Medical and Health Services, Jaipur
Email: jdmh-bik-rj@nic.in, Contact Number: 9414171874

DIPR\C\18110\2026

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक कैलाश त्रिवेदी के लिए उदय प्रिन्टर्स 43-ए, माली कॉलोनी चांदपोल बाहर जयपुर से मुद्रित एवं डी-38, प्रधानपथ, चौमू हाउस, सी स्कीम, जयपुर से प्रकाशित। सम्पादक कैलाश त्रिवेदी* । *पीआईबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार।
फोनः 0141-4038281, **Email:-** lokjeewanjpr@gmail.com **भीलवाड़ा कार्यालयः** 207-214, नागौरी गार्डन, लोकजीवन कॉम्पलेक्स, भीलवाड़ा। **फोनः** 01482-355985, Email:- lokjeewan@gmail.com, **मो.** 8306792625